शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

# शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-2 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 9-16 जनवरी 2023 मूल्य पांच रूपए

# सरकार फिजूलखर्ची को कैसे चिन्हित और परिभाषित करेगी गारन्टियों पर फैसलों से उठी चर्चा

- क्या वितिय कुप्रबन्धन के लिये केवल राजनीतिक नेतृत्व ही जिम्मेदार रहे हैं?
- क्या संबद्ध प्रशासन की इसमें कोई भूमिका नही है?
- क्या मुख्य संसदीय सचिव प्रशासनिक अनिवार्यता है या राजनीतिक विवशता?
- क्या कुप्रबंधन की भरपायी बयानों से ही हो जायेगी?
- एक की राहत के लिये दूसरे को टैक्स करना कितना सही है?

**शिमला/शैल।** सुक्खू सरकार ने अपनी सरकार की पहली ही मन्त्रीमण्डल बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों के लिये पुरानी पैन्शन योजना बहाल कर दी है। इससे राज्य को 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे और सरकार पर इसी वर्ष इसके लिये करीब 900 करोड़ का बोझ पड़ेगा। मुख्यमन्त्री ने पत्रकार वार्ता में दावा किया है कि इसके लिये धन का प्रबन्ध सरकार की फजूल खर्चों पर लगाम लगाकर किया जायेगा। मन्त्रीमण्डल की इसी बैठक में महिलाओं को पन्द्रह सौ रुपए प्रतिमाह देने और युवाओं को एक लाख रोजगार उपलब्ध करवाने के फैसलों पर भी मोहर लगा दी गयी है। इन फैसलों के लिए विस्तृत योजनाएं बनाने को लेकर दो मन्त्री स्तरीय कमेटियों का भी गठन कर दिया गया है और यह कमेटीयां एक माह के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार में जनता को दस गारंटियां दी थी और यह वायदा किया था कि उक्त तीनों फैसलों को मन्त्रीमण्डल की पहली ही बैठक में लागू कर दिया जायेगा। सुक्खू सरकार ने यह फैसले लेकर पार्टी के वायदों पर अमल किया है और यह पार्टी की विश्वसनीयता बढ़ाने में लाभप्रद होगा ऐसा माना जा रहा है।

अभी सरकार को सत्ता संभाले एक माह का समय हुआ है और सरकार को पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करना है। इसलिये सरकार के हर फैसले और हर वक्तव्य पर पहले दिन से नजर बनाये रखना आवश्यक होगा। क्योंकि इसका प्रभाव कार्यकाल के अन्त तक बराबर बना रहेगा। यहां यह भी उल्लेखनीय रहेगा कि उसका भाजपा जैसे विपक्ष से आमना-सामना रहेगा। मुख्यमन्त्री और उप मुख्यमन्त्री की शपथ के बाद दूसरे ही दिन सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार के पिछले छः माह में लिये गये फैसलों पर रोक का आदेश जारी कर दिया। भाजपा इस पहले ही फैसले के खिलाफ सड़कों पर आ गयी और इसे चुनौती देते हुये प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका तक दायर हो गयी है। इसके बाद पहले ही मन्त्रीमण्डल विस्तार में छः मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां करके एक और वैधानिक मुद्दा सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। कानून की जानकारी रखने वालों के मुताबिक इन नियुक्तियों की आवश्यकता नहीं थी। इन फैसलों का प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा।

नयी विधानसभा का पहला सत्र धर्मशाला में विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह से शुरू हुआ है। इस सत्र में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर सदन की शपथ से पहले ही नेता प्रतिपक्ष चुने जा चुके थे और मान्यता पा चुके थे। ऐसा पहली बार हुआ है। इसी सत्र में पिछली सरकार से विरासत में करीब 75000 करोड़ का ऋण मिलने और 600 करोड़ का धन बिना अनुमतियों और प्रावधानों के खर्च किये जाने का खुलासा भी सामने आया है। पिछली सरकार पर घोर वित्तीय कुप्रबन्धन का आरोप भी लगा है। इसी सबके साथ डीजल पर तीन रूपये प्रति लीटर वैट बढ़ाये जाने का फैसला भी जनता के सामने आया और तर्क यह दिया गया कि पिछली सरकार ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह वैट घटाया था। इसलिये पिछली सरकार के छः माह के फैसलों के दायरे में आने के कारण इसे भी पलट दिया गया। इसमें सरकार यह भूल गयी कि इससे आम आदमी को राहत मिली थी। अब यह तर्क दिया गया है कि इस वैट से होने वाली आय से 1.36 लाख कर्मचारियों को ओ.पी.एस. देने का प्रयोग किया जायेगा। इससे यह भी संकेत उभरता है कि हर राहत की भरपायी जनता से परोक्ष/अपरोक्ष में की जायेगी।

उद्योग मन्त्री हर्षवर्धन चौहान के बयान के मुताबिक सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत नाजुक है। दैनिक खर्चे चलाने के लिये भी पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। विधानसभा सत्र में भी पिछली सरकार पर भारी वितिय कुप्रबंधन का आरोप लगा है। कुप्रबन्धन के बहुत सारे खुलासे कैग रिपोर्टों में दर्ज हैं। कांग्रेस अपना आरोपपत्र ''लूट की छूट'' के नाम से चुनाव प्रचार के दौरान जारी कर चुकी है। लेकिन अभी इस लूट की ओर कोई कारवाई किये जाने का संकेत तक सामने नही आया है। ऐसे में यह सवाल उभरने स्वभाविक है कि सरकार फिजूल खर्चो को चिन्हित कैसे करेगी? गारन्टीया पूरी करने के लिये किस वर्ग को कितना टैक्स करेगी? यदि पिछली सरकार के समय में भारी वित्तीय कुप्रबन्धन हुआ है तो क्या इसके लिये अकेले राजनीतिक नेतृत्व को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या इसमें संवद्ध अफसरशाही की कोई जिम्मेदारी नही है? क्या इस कुप्रबन्धन की भरपाई केवल ब्यान देने मात्र से ही हो जायेगी? यदि कैग रिपोर्ट के आधार पर स्व. बी.एस. थिंड के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है तो उसी तर्ज पर और रिपोर्टों के आधार पर औरों के खिलाफ क्यों नही? सरकार फिजूल खर्ची रोकने की बात कर रही है। क्या मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां प्रशासनिक बाध्यता है और इस बाध्यता को पूर्व सरकार ने पूरा न करके कोई वैधानिक अपराध किया था या यह नियुक्तियां एक राजनीतिक विवशता बन गयी है? जनता में यह चर्चा का विषय बनता जा रहा है और इसके सामने फिजूलखर्ची चिन्हित और परिभाषित करना आसान नही होगा। क्योंकि जनता ने महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित होकर कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में चुना है। यदि यह विकल्प भी व्यवस्था परिवर्तन के दावों के बीच पुरानी ही लकीरों को लम्बा करता रहा हम तो जनता के लिए घातक होगा और इसके परिणाम भी घातक हो होंगे?

# मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश विधि विश्वविद्यालय के कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति न्यायमूर्ति अमजद ए. सईद ने शिमला के समीप घंडल में हिमाचल प्रदेश विधि विश्वविद्यालय के 'ऋषिका संघमित्र' कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया। इस छात्रावास के

निर्माण पर लगभग 14.50 करोड़ की धनराशि व्यय की जाएगी।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए पर्याप्त अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से छात्रों की सुविधा के लिए एक ब्वॉयज हॉस्टल निर्मित करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध होते ही 5 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करेगी। उन्होंने विद्यार्थियों को आवास की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को छात्रावासों के अच्छे डिजाइन तैयार करने को कहा।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पर 75,000 करोड़ रुपये से अधिक का भारी वित्तीय बोझ है। इसके बावजूद राज्य सरकार बेहतर अधोसंरचना स्थापित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को विस्तार प्रदान करने के लिए अतिरिक्त 25 बीघा भूमि के लिए वन स्वीकृतियां शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के सहयोग से हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, हाइड्रो और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष नीति ला रही है ताकि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश को कर्ज के बोझ से बाहर निकालकर राज्य को प्रगति और समृद्धि के पथ अग्रसर करने के लिए कर्मचारियों और समाज के हर वर्ग क सक्रिय सहयोग वांछित है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के प्रथम आग्रह पर ही विधि विश्वविद्यालय का दौरा किया और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया ताकि यह विधि विश्वविद्यालय देश का प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट संस्थान बनकर उभरे।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद ए. सईद ने इस अवसर पर कहा कि विश्वविद्यालय के लिए यह गर्व का क्षण है कि विश्वविद्यालय परिसर में एक विश्व स्तरीय कन्या छात्रावास बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के उचित संरक्षण और सहयोग से ही शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र विकसित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को छात्र और छात्राओं के लिए लगभग छह छात्रावासों निर्मित करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी। उन्होंने विश्वविद्यालय में बेहतर अधोसंरचना सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. निष्ठा जसवाल ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने विश्वविद्यालय की विभिन्न उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला और विश्वविद्यालय की कुछ मांगों को भी विस्तापूर्वक उठाया।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. एस.एस. जसवाल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा, न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन, प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव विधि राजीव भारद्वाज, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग अजय गुप्ता, लोक निर्माण विभाग के चीफ आर्किटेक्ट राजीव शर्मा, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग सुरेश कपूर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

# राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी व मकर सक्रांति की बधाई दी

**शिमला/शैल।** राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी व मकर सक्रांति के पावन अवसर पर बधाई दी है।

राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि यह त्यौहार लोगों के जीवन में खुशहाली व समृद्धि का प्रतीक हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोहड़ी का यह त्यौहार सभी बुराईयों को समाप्त कर प्रदेशवासियों के जीवन में प्रसन्नता एवं बेहतर स्वास्थ्य लेकर आएगा।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों विशेषकर बेसहारा बच्चों, महिलाओं तथा वृद्धजनों को लोहड़ी की बधाई दी। उन्होंने आशा जताई कि सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे उत्सव अनुदान से बेसहारा बच्चों, महिलाओं तथा वृद्धजनों के चेहरों पर मुस्कान आएगी और उनकी लोहड़ी भी विशेष बनेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के उत्सव जहां एक ओर परिजनों के साथ खुशियां सांझा करने का अवसर प्रदान करते हैं वहीं इनसे आपसी भाईचारा भी मजबूत होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह त्यौहार उत्सव एवं खुशियों के साथ-साथ नई फसल के आगमन का भी प्रतीक है।

# धार्मिक स्थलों में ई-परिवहन सुविधा को दिया जाएगा बढ़ावा:मुकेश अग्निहोत्री

**शिमला/शैल।** विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए स्कूलों में आधारभूत ढांचा विकसित करवाया जाएगा। यह बात हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत एसडी पब्लिक सीनियर सेकंडरी स्कूल

पालकवाह में आयोजित वार्षिक पारितोषिक पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही। इस मौके पर उन्होंने स्कूल की वार्षिक गतिविधियों में अव्वल रहे बच्चों को सम्मानित भी किया।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र का विकास और गरीब लोगों की सेवा ही उनका मुख्य ध्येय है। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में तीन डिग्री कॉलेज के माध्यम से लड़कियों को घर-द्वार पर ही उच्च शिक्षा प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि खड्ड कॉलेज को नई बिल्डिंग में स्थानांतरित करने के साथ ही हरोली कॉलेज को इस वर्ष के अन्त तक तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा हरोली क्षेत्र में 33 सीनियर सेकंडरी स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा रही है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की प्रवृति को रोकने के लिए स्कूलों के समीप शराब के ठेकों को शीघ्र बंद किया जाएगा ताकि बच्चों को पढ़ाई का अच्छा वातावरण मिल सके। उन्होंने शिक्षकों तथा अभिवावकों का आहवान किया कि बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कारों से परिचित करवाएं ताकि देश निर्माण में वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली की जनता को सीधा ऊना से जोड़ने के लिए प्रदेश का सबसे लंबा पुल तैयार करके जनता को सौंपा गया, जिससे साथ लगते सभी गावों को बेहतर सुविधा मिली है। स्थानीय जनता की सुविधा के लिए पंडोगा-त्यूड़ी पुल का निर्माण शीघ्र ही किया जाएगा।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य में सिंचाई के साथ-साथ पेयजल की नई योजनाएं निर्मित करवाना उनकी प्राथमिकता है ताकि प्रदेश में कोई भी क्षेत्र पानी की सुविधा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। हरोली हल्के में भी धार्मिक स्थलों का सौन्दर्यकरण किया जाएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को ईसपुर से मंदिर दमामियां सड़क का कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ई-वाहनों के संचालन को बढ़ावा दिया जाएगा और चिंतपूर्णी सहित राज्य के मुख्य धार्मिक स्थलों में परिवहन की इस नई सुविधा को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरोली क्षेत्र की महिलाओं को प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी करवाया जाएगा।

मुकेश अग्निहोत्री ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए स्थानीय स्कूल को 51 हजार रूपये देने की घोषणा की।

इससे पूर्व स्कूल के प्रधानाचार्य संदीप अग्निहोत्री ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

इस अवसर पर एसडीएम हरोली विशाल शर्मा, उपनिदेशक आरम्भिक शिक्षा देवेंद्र चंदेल, स्कूल के प्रबन्ध निदेशक सुखदेव दत्त, जिला प्रधान रणजीत राणा, प्रदेश कांग्रेस सचिव सतीश बिट्टू, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनोद बिट्टू, कैप्टन शक्ति चंद सहित स्कूल का समस्त स्टाफ, अभिभावकगण और भारी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
अंजना

# वार्षिक बजट की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए बैठकों का आयोजन

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 30 और 31 जनवरी, 2023 को वार्षिक बजट 2023-24 के लिए विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विधायकों के साथ दो दिवसीय बैठकों का आयोजन हिमाचल प्रदेश सचिवालय आर्मजडेल भवन के कांफ्रेंस हाल में किया जाएगा।

30 जनवरी, 2023 को पूर्वाहन 10.30 बजे से 1.30 बजे तक चम्बा, शिमला और लाहौल-स्पीति तथा अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिले के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएंगी।

31 जनवरी, 2023 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से 1.30 बजे तक कांगड़ा व किन्नौर जिलों तथा अपराह्न 2 से 5 बजे तक सोलन, बिलासपुर तथा मण्डी के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।

इन बैठकों में वार्षिक बजट 2023-24 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा।

बैठकों में विधायकों से वर्ष 2023-24 के लिए मित्तव्ययता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने एवं बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा होगी।

# मुख्यमंत्री व उप-मुख्यमंत्री ने सेना के जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त किया

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जम्मू-कश्मीर के माछिल सैक्टर में 14 डोगरा रेजीमेंट के तीन जवानों की शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। इनमें से दो जवान हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे।

जिला एवं तहसील हमीरपुर के गांव तलासी खुर्द के जवान अमित शर्मा (23) पुत्र विजय कुमार तथा ऊना जिला की धनारी तहसील के मंडवारा गांव के हवलदार अमरीक सिंह (39) जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के माछिल सैक्टर में तैनात थे नियमित गश्त के दौरान उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया।

मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से शहीदों के परिवार के सदस्यों को संकट की इस घड़ी में हर संभव मदद का भरोसा दिया है।

उन्होंने दुर्घटना में शहीद जम्मू के मजुआ उत्तमी गांव के नायब सूबेदार पुरूषोत्तम कुमार की शहादत पर भी गहरा दुःख व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी शहीद हुए इन जवानों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सेना के जवानों एवं भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं का हमेशा सम्मान करती है और राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।

# कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाने का निर्णय

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास जताने पर प्रदेश

के लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया।

मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उनके गतिशील और सशक्त नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया जिसके फलस्वरूप प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में पार्टी को शानदार जीत हासिल हुई है।

मंत्रिमंडल ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाने का भी निर्णय लिया और सभी संबंधित मंत्री व सचिव और विभागाध्यक्ष इसे अक्षरश: लागू करेंगे।

मंत्रिमंडल ने वर्तमान में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना जिसे एनपीएस भी कहा जाता है, के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से राज्य के लगभग 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमंडल ने कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान राज्य में एक लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के वायदे को लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडल ने 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये देने के कांग्रेस पार्टी के चुनावी वायदे के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया।

# वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम के आवासियों तथा वंचितों को मिलेगा वस्त्र अनुदान

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के बसंतपुर स्थित वृद्धाश्रम का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम में रह रहे आवासियों, निराश्रित

महिलाओं एवं मूकबधिर बच्चों इत्यादि के लिए 10 हजार रुपये प्रति आवासी प्रति वर्ष वस्त्र अनुदान प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी एवं सर्दियों के वस्त्रों के लिए पांच-पांच हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इससे समाज वंचित लोगों को बेहतर कपड़े उपलब्ध होंगे। उन्होंने आवासियों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सम्बन्धित अधिकारियों को इन संस्थानों के आवासियों के साथ प्रमुख त्यौहार मनाने के निर्देश दिए ताकि इनमें अपनत्व का भाव जागृत हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम के आवासियों तथा निराश्रित महिलाओं को 500 रुपये उत्सव अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ताकि ये लोग भी प्रदेश के अन्य लोगों की तरह त्यौहारों को मना सकें। इससे पहले मुख्यमंत्री का धामी, टिक्करघाटी, मांदरी, बागीपुल इत्यादि स्थानों पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। व्यापार मंडल सुन्नी ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

# निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गठित होगा समर्पित निवेश प्रोत्साहन एवं सुगमता ब्यूरो:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को निवेश का मुख्य गंतव्य बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में एक समर्पित निवेश प्रोत्साहन एवं सुगमता ब्यूरो का गठन किया जायेगा। इस ब्यूरो के माध्यम से सभी स्वीकृतियां समयबद्ध ढंग से प्रदान की जाएंगी, जिससे राज्य में निवेश की गति को और बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ब्यूरो उद्योग, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आयुर्वेद, सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटीईएस, ऊर्जा तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस ब्यूरो के संचालन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क के विकास, एवं संचालन के लिए भी रणनीतिक निवेशक के चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने तथा इसके लिए सलाहकार की शीघ्र नियुक्ति के निर्देश दिए।

बैठक में प्रधान सचिव, उद्योग आर.डी. नज़ीम ने प्रस्तावित निवेश प्रोत्साहन एवं सुगमता ब्यूरो के गठन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित ब्यूरो के माध्यम से 10 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को अनुमोदन एवं स्वीकृतियां प्रदान की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि ब्यूरो में सभी मुख्य विभागों के वरिष्ठ विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्ति आधार पर तैनात किया जाएगा ताकि सभी स्वीकृतियां समयबद्ध प्रदान की जा सकें।

निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आई.टी. पार्क के लिए स्थल चयन के उद्देश्य से विभाग के अधिकारियों के एक दल ने धर्मशाला तथा आस-पास के क्षेत्रों का दौरा किया है। बैठक में उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

# सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने का निर्देश:उद्योग मंत्री

**शिमला/शैल।** उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राज्य की सभी औद्योगिक परियोजनाओं, खनन और हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एच.पी.एस.आई.डी.सी) की गतिविधियों की समीक्षा की।

हर्षवर्धन चौहान ने उद्योग विभाग को राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने

कहा कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए विशाल भू-बैंक की तत्काल आवश्यकता है, इसलिए भूमि हस्तांतरण के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए उचित प्रयास किए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद बदलते वैश्विक परिदृश्य में विनिर्माण का एक बहुत बड़ा भाग चीन से विश्व के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित हो रहा है। इसलिये निवेश को आकर्षित करने के दृष्टिगत विभाग को उदार और निवेशक हितैषी नीतियों के साथ-साथ संभावित निवेशकों के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित करना चाहिए।

उद्योग मंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी स्वीकृतियों एवं अनापत्तियों के लिए सिंगल रूफ प्लेटफॉर्म बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों के सभी नियमों और विनियमों का अध्ययन करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर इन्वेस्ट ब्यूरो डाक्यूमेंट तैयार करने के भी निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि नीति समर्थन, जागरूकता और विस्तृत कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में ग्रामीण उद्यमों को प्रोत्साहित करने की संभावना भी तलाशी जानी चाहिए। राज्य में स्टार्ट-अप कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के अधिक से अधिक तकनीकी संस्थानों को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों से नियमित संवाद पर विशेष बल दिया जाए और युवाओं के लिए ऐंजल इन्वेस्टर फंड जुटाने का प्रयास किया जाए।

इस अवसर पर खनन गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उद्योग मंत्री ने राजस्व बढ़ाने और अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 15 दिनों के भीतर स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व चोरी एवं अवैध खनन गतिविधियों के विरूद्ध सख्त कारवाई की जाये।

इससे पूर्व, निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें विभाग की संगठनात्मक संरचना, औद्योगीकरण का मूल जनादेश, वर्तमान में जारी खनन गतिविधियां, समग्र औद्योगिक परिदृश्य, भू-बैंक, सभी लंबित परियोजनाएं जिन पर ग्लोबल इन्वैस्टर मीट 2019 के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और प्रमुख कार्यक्रम जैसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, एमएसएमई क्लस्टर परियोजनाएं, प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइसिस व राज्य खाद्य मिशन कार्यक्रम शामिल थे। इस दौरान आगामी औद्योगिक इन्फ्रा परियोजनाओं, मेडिकल डिवाइसिस पार्क और बल्क ड्रग फार्मा पार्क पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

प्रमुख सचिव उद्योग आरडी नजीम ने आश्वासन दिया कि सभी निर्देशों को अक्षरश: लागू किया जाएगा और वर्तमान में जारी सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा।

बैठक में उद्योग विभाग, खनन, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम और सामान्य उद्योग निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

# मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए आपदा कोष में वृद्धि करने का आग्रह किया

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह द्वारा नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के लिए दो डॉपलर वेदर राडार

स्थापित करने के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के लिए आपदा कोष में वृद्धि करने का आग्रह किया क्योंकि राज्य अपनी कठिन भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है।

यह राडार प्रदेश के मंडी जिले के मुरारी देवी व चंबा जिले के जोत में स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राडार विशेषकर कम दूरी के पूर्वानुमानों के लिए सभी दिशाओं में 100 किलोमीटर के दायरे में भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की जानकारी देने में सक्षम होंगे। ये राडार राज्य के लिए क्षेत्र विशिष्ट पूर्वानुमान और चेतावनी में सुधार करने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि ये मौसम की निगरानी क्षमताओं में वृद्धि करेंगे और सटीक डाटा उपलब्ध करवाएंगे जिससे प्रशासन को मौसम के कारण होने वाली आपदाओं के नुकसान को कम करने के लिए पूर्व प्रबंधन में सहायता मिलेगी।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला जिले के कुफरी में 15 जनवरी, 2021 को एक डॉपलर वेदर राडार पहले ही स्थापित किया जा चुका है और इन दो अतिरिक्त राडारों के क्रियाशील होने से राज्य का लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र मौसम पूर्वानुमान के दायरे में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी भी किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों का लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र इन राडार के दायरे में नहीं आएगा।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय राज्य मंत्री से इन जिलों के लिए अतिरिक्त राडार उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि इन जनजातीय जिलों को भी कवर किया जा सके। उन्होंने कहा कि हाल ही के वर्षों में बादल फटने से किन्नौर जिले में भारी नुकसान हुआ है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि पहले से निवारक उपाय करने के लिए एक उचित मौसम पूर्वानुमान तंत्र विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि बादल फटने की इन घटनाओं से बिजली परियोजनाओं संबंधी क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है, जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नही होता।
..... स्वामी विवेकानंद

## सम्पादकीय

# क्या हिमाचल जोशीमठ त्रासदी से सबक लेगा

जोशीमठ धंस रहा है। घरों और सड़कों तक हर जगह दरारें आ गयी हैं। यहां रहना जोखिम भरा हो गया है। पीड़ितों और प्रभावितों को दूसरे स्थानों पर बसाना प्राथमिकता बन गया है। देश के हर नागरिक का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है और इसी से कुछ राष्ट्रीय प्रश्न भी उभर कर सामने आये हैं। यह सवाल उठ रहा है कि क्या जोशीमठ की यह त्रासदी अचानक घट गयी जिसका कोई पूर्व आभास ही नहीं हो पाया या फिर विकास के नाम पर पूर्व चेतावनीयों को नजरअन्दाज करने का यह परिणाम है ? क्या देश के सभी पर्यटक स्थल बने हिल स्टेशनों की देर सवेर यही दशा होने वाली है ? जोशीमठ क्षेत्र के विकास को लेकर एक समय संसद के अन्दर स्व. श्रीमती सुषमा स्वराज का वक्तव्य इस दिशा में बहुत कुछ कह जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के क्या मानक होने चाहिये इस पर दर्जनों भूवैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के शोध उपलब्ध हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण के क्या मानक होनी चाहिये? प्रदूषण के विभिन्न पक्षों को कैसे नियंत्रित और सुनिश्चित किया जायेगा इसके लिए केन्द्र से लेकर राज्यों तक सभी जगह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन हो चुका है। बड़ी परियोजनाओं की स्थापना से पहले उन्हें पर्यावरण से जुड़ी हर क्लीयरैन्स हासिल करना अनिवार्य है। जोशीमठ का जब विकास हो रहा था और उस क्षेत्र में बड़ी परियोजनाएं स्थापित की जा रही थी और बड़ी-बड़ी सुरंगों का निर्माण हो रहा था तब यह सारे अदारे वहां कार्यरत थे। आज जोशीमठ क्षेत्र की इस त्रासदी के लिये इन्हीं परियोजना और निर्माणों को मूल कारण माना जा रहा है। इस परिपेक्ष में यह सवाल जवाब मांगता है कि जब यह विकास हो रहा था बड़ी परियोजनाओं और सुरंगे बन रही थी तब क्या इन अदारों ने पर्यावरण और विज्ञान से जुड़ी सारी अनिवार्यताओं की पूर्ति सुनिश्चित की थी या नहीं? क्या बाद में किसी के प्रभाव/दबाव में आकर इन अनिवार्यताओं की सुनिश्चितत्ता से समझौता कर लिया गया? इस समय इस पक्ष पर निष्पक्षता से जांच की आवश्यकता है। ताकि दोषियों को सार्वजनिक रूप से अनुकरणीय सजा दी जा सके।

आज जोशीमठ की तर्ज पर ही हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्र ऐसी ही आपदा के मुहाने पर खड़े हैं। प्रदेश के आपदा सूचना प्रवाह प्रभाग की सूचनाओं के अनुसार पिछले करीब दो वर्षों से प्रदेश के विभिन्न भागों में प्राय: औसतन हर रोज एक न एक भूकंप आ रहा है। प्रदेश भूकंप जोन पांच में है। सरकार की अपनी रिपोर्टों के मुताबिक राजधानी नगर शिमला भूकंप के मुहाने पर बैठा है।

1971 में शिमला के लक्कड़ बाजार क्षेत्र में जो नुकसान हुआ था उसके अवशेष आज भी उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक रिज का एक हिस्सा हर वर्ष धंसाव का शिकार हो रहा है। इस स्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुये एन.जी.टी. ने नये निर्माणों पर रोक लगा रखी है। लेकिन एन.जी.टी. की इस रोक की अवहेलना स्वयं सरकार और मुख्यमन्त्री के सरकारी आवास से शुरू हुई है। एन.जी.टी. के फैसले के बाद हजारों भवन ऐसे बने हैं जो इन आदेशों की खुली अवहेलना हैं। पिछली सरकार एन.जी.टी. के आदेशों को निष्प्रभावी बनाने के लिये शिमला का विकास प्लान लेकर आयी थी। लेकिन एन.जी.टी. ने इस प्लान को रिजैक्ट कर दिया है। इस कारण फैसले के बाद बने हजारों मकानों पर नियमों की अवहेलना के तहत कारवायी होनी है। लेकिन वोट की राजनीति के चलते कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आकर ऐसी कारवायी करने से बचना चाहता है। जबकि सरकार की अपनी ही रिपोर्ट के मुताबिक शिमला में भूकंप के हल्के से झटके में ही तीस हजार से ज्यादा लोगों की जान जायेगी और अस्सी प्रतिशत निर्माणों को नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि हिमाचल सरकार जोशीमठ से कोई सबक लेती है या नहीं।

# खतरनाक है आत्मघाती हमले और बम धमाकों पर उलेमाओं की खामोशी

गौतम चौधरी

इस साल नवम्बर के महीने में नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के प्रमुख उलेमाओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में मुस्लिम समाज में उग्रवाद और आतंकवाद से लड़ने के तरीकों पर चर्चा भी की गयी लेकिन, दोनों मुल्कों के उलेमाओं ने दुनियाभर में हो रहे हालिया गैर-इस्लामिक आतंकवादी हमले की न तो निंदा की और न ही ऐसे कोई बयान जारी किये जिससे इस्लाम के नाम पर आतंक फलाने वाले मौकापरस्थ हतोतसाहित हो पायें। वर्तमान समय में आईएसआईएस और अलकायदा आदि बड़े आतंकवादी संगठनों के द्वारा कोई बड़ा आक्रमण तो नहीं हो रहा है लेकिन आतंकवादियों के हौसले बुलंद हैं। तथ्य से स्पष्ट है कि इस साल नवम्बर और दिसम्बर के महीने में इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया आदि कई इस्लामिक देशों में कई बम विस्फोट किये गये और आत्मघाती हमले किये गये। इन हमलों में कई निर्दोष छात्र, श्रमिक, महिला, बच्चे आदि मारे गए। इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि इस्लामिक देशों में आत्मघाती बम विस्फोट और बम विस्फोट आम बात हो गई है। अधिकांश आतंकवादी हमले लावारिस होते हैं क्योंकि आतंकवादी जानते हैं कि उनका कृत्य गैर-इस्लामिक और अमानवीय है।

इस प्रकार की गैर-इस्लामिक कृत्यों के बावजूद भी हिंसा और आतंकवाद की ऐसी घटनाओं की निंदा करने के लिए सामूहिक मुस्लिम धार्मिक नेतृत्व की ओर से निंदा का कोई बयान जारी नहीं किया गया। जबकि इस्लामी देशों के लिए इस प्रकार की गैर-मानवीय घटना बेहद खतरनाक होती जा रही है। इसके कारण ज्यादातर मुसलमान ही मारे जाते हैं। गैर-मुसलमानों की संख्या बहुत कम होती है बावजूद इसके उलेमा इस बात को लेकर चर्चा करने से कतराते हैं कि इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद खड़ा किया गया है उसे खत्म कर देनी चाहिए, चुनांचे यह इस्लाम की मूल भावना को हानि पहुंचा रहा है।

आतंकवाद के मामले में वैश्विक मुस्लिम मुफ्ती और उलेमा एक साथ आने में विफल रहे हैं क्योंकि धार्मिक अतिवाद और आतंकवाद पर उनके विचार अलग अलग हैं। वास्तव में, आईएसआईएस को शियाओं के दुश्मन के रूप में देखा जाता है। सुन्नी उलेमाओं का एक समूह इसका समर्थन करता है और सुन्नी मुसलमान युवकों को इसके साथ जुड़ने का आहवान भी करते हैं। यह कहीं-कहीं प्रत्यक्ष होता है तो कहीं-कहीं परोक्ष होता है। यानी सुन्नी उलेमाओं के एक समूह का आईएसआईएस को समर्थन प्राप्त है। विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित सुन्नी विद्वानों के एक समूह ने वर्ष 2014 में खुले तौर पर आईएसआईएस का समर्थन कर दिया था। शियाओं और अहमदियों को कई सुन्नी उलेमाओं ने काफिर घोषित कर रखा है और उनके खिलाफ सार्वजनिक नरसंहार का फतवा जारी कर दिया है। मस्जिदों और मदरसों पर हमले सांप्रदायिक टकराव के कारण किये जाते हैं और ऐसे हमलों के पीछे उलेमा द्वारा जारी कुफ्र के फतवे ही होते हैं। यही कारण है कि उलेमा तब चुप रहते हैं जब किसी मस्जिद या मदरसे पर हमला किया जाता है और बच्चों सहित बड़े पैमाने पर निर्दोष मुसलमान मारे जाते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आज मुस्लिम समाजों में हिंसा के अधिकांश मामलों के मूल में सांप्रदायिक और उग्रवादी वह विचारधारा है जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है लेकिन वह सब इस्लाम के नाम पर हो रहा है।

मस्जिदों, मदरसों, सार्वजनिक स्थानों और थानों में आत्मघाती हमले और बम विस्फोटों पर उलेमा की चुप्पी उनकी वैचारिक दुविधा को प्रकट करती है। यदि वे हिंसा की इन घटनाओं को हराम घोषित करते हैं, तो वे अपने शिक्षकों के फतवों और विचारों को नकार देंगे। उन्हें इस बात का भी डर है कि अगर वे इस मुद्दे पर लीक से हटकर बयान देते हैं तो उनके साथी संप्रदाय के उलेमा नाराज हो जाएंगे। यह एक विडंबना है कि पवित्र कुरान मुसलमानों को ऐसे आतंकवादियों और चरमपंथियों से लड़ने और दंडित करने के लिए कहता है, लेकिन मुसलमानों द्वारा सांप्रदायिक आधार पर मदरसों में बच्चों की हत्या पर पूरा मुस्लिम नेतृत्व खामोश रहता है। यह तबका तब हाइबरनेशन से बाहर आता है, जब कोई गैर-मुस्लिम पैगम्बर या कुरान के खिलाफ टिप्पणी करता है, निंदा के बयान जारी करता है और यहां तक कि मुसलमानों को इस्लाम के दुश्मन के खिलाफ कारवाई करने के लिए उकसाता है। हालांकि कुरान उन्हें ऐसी बातों को नजरअंदाज करने के लिए कहता है, बावजूद इसके वे अपने चरमपंथ पर डटे हुए होते हैं।

उलेमा और मुस्लिम बुद्धिजीवियों/विद्वानों/मौलवियों सहित सभी मुस्लिम नेतृत्व को अपने वैचारिक या सांप्रदायिक मतभेदों से खुद को दूर रखते हुए उग्रवाद, हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ एक एकजुट रुख अपनाने की जरूरत है। इसके अलावा आत्मघाती हमलों और बम विस्फोटों को हराम और गैर-इस्लामी करार देने की जरूरत है। अगर ये विद्वान आज भी चुप रहे तो इस्लाम को हानि होगी। मैं समझता हूं कि केवल इस्लाम को ही नहीं पूरी मानवता की हानि होगी क्योंकि इस्लाम केवल मुसलमानों का ही नहीं है। यह चिंतन पूरी मानव जाति को निर्देशित और संरक्षित करने का चिंतन है। इसलिये इसे बचाना और इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना उन उलेमाओं के हाथ में हैं जो अपने आप को खुदा के नेक बंदे कहलाने में फक्र करते हैं।

# देश के 651 जिलों में खुलेंगे जनऔषधि केंद्र

**शिमला।** सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत देश भर में पहले से ही 9000 से अधिक जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं। सरकार ने मार्च 2024 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। पीएमबीजेपी के उत्पाद बास्केट में सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों को कवर करने वाली 1759 दवाएं तथा 280 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं।

सरकार ने इस उद्देश्य के साथ विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 651 जिलों में नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए पीएमबीजेपी की कार्यान्वयन एजेंसी, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

यह योजना स्थायी और नियमित आय के साथ स्वरोजगार का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। पीएमबीजेपी के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों को वित्तीय सहायता के रूप में 5.00 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीप क्षेत्रों तथा नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित पिछड़े क्षेत्रों या महिला उद्यमी, पूर्व सैनिक, दिव्यांग जनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति द्वारा खोले गए जन औषधि केंद्रों को 2.00 लाख रूपये का एकमुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन (आईटी और अवसंरचना व्यय के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में) प्रदान किया जाता है।

# वायदों को निभाया, जन-जन में विश्वास जगाया
# सुक्खू सरकार ने जन-जन का जीवन सुखमय बनाया

**शिमला।** जीवन के प्रत्येक पग पर संघर्ष के साथ अनुभव को प्राप्त कर हिमाचल के मुख्यमन्त्री पद पर सुशोभित सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊर्जावान नेतृत्व में प्रदेश में नई सरकार का गठन सभी हिमाचलवासियों के जीवन में प्रसन्नता लाया है।

मुख्यमन्त्री ने अपनी दूरदर्शी सोच और प्रदेश को विकास के नवीन क्षितिज पर स्थापित करने के संकल्प के साथ समाज के सभी वर्गों को आत्मसम्मान के साथ जीने का मन्त्र प्रदान कर हिमाचल में एक नवीन शुरुआत की है।

प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने अपनी प्रथम बैठक में वायदे के अनुरूप न केवल पुरानी पैन्शन व्यवस्था को बहाल किया अपितु महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये प्रदान करने और रोज़गार के 1 लाख अवसर सृजित करने के लिए मन्त्रिमण्डलीय उप-समितियां गठित कर इन्हें अपनी रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रदान करने के निर्देश देकर यह सुनिश्चित बनाया कि इतिहास में इस सरकार को वायदे निभाने के लिए सदैव याद रखा जाएगा न कि पूर्ववर्ती सरकार की तरह जिन्होंने अपने कार्यकाल के अंत में चुनाव के दृष्टिगत बिना बजटीय प्रावधान के लगभग 900 विभिन्न संस्थान खोले।

पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने से प्रदेश के उन एक लाख 36 हजार कर्मचारियों वह सम्बल प्राप्त हुआ, जो उन्हें वृद्धावस्था में आत्मसम्मान के साथ जीवनयापन का अधिकार प्रदान करेगा। प्रदेश में 20 वर्ष उपरान्त पुरानी पैन्शन को बहाल करने का निर्णय निःसंदेह मुख्यमन्त्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यकुशलता का परिचायक है।

मुख्यमन्त्री ने सत्ता सम्भालते ही समाज के कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों को सहारा प्रदान करने की दिशा में सार्थक प्रयास आरम्भ किये। उन्होंने सर्वप्रथम शिमला के टुटीकण्डी स्थित बालिका आश्रम में जाकर इन बालिकाओं को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए विभिन्न आश्रमों में और अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। बालिकाओं एवं अन्य निराश्रित जन की संस्थागत देखभाल के लिए बाल देखभाल संस्थाओं, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और वृद्धा आश्रमों के आवासियों को मुख्य त्यौहार मनाने के लिए 500 रुपये का उत्सव अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत संचालित की जा रही बाल संरक्षण इकाइयों, वृद्धाश्रमों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन इत्यादि और विशेष गृह में लोहड़ी व मकर संक्रांति (माघी) तथा होली उत्सवों को मनाने के निर्देश भी जारी किए ताकि यह सभी अपने आपको समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित मानें।

मुख्यमन्त्री ने समाज के वंचित वर्गों के लिए एक और निर्णय लिया कि प्रदेश सरकार वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम में रह रहे आवासियों, निराश्रित महिलाओं एवं मूकबधिर बच्चों इत्यादि के लिए 10 हजार रुपये प्रति आवासी प्रति वर्ष वस्त्र अनुदान प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने शिमला ज़िला के बसन्तपुर स्थित वृद्धाश्रम का दौरा करने के उपरान्त यह निर्णय भी लिया कि इन सभी श्रेणियों को 5000 रुपये शीत तथा 5000 रुपये ग्रीष्म वस्त्र भत्ते के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

जरूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान कर उनका भविष्य सुरक्षित बनाने एवं निराश्रित महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 101 करोड़ रुपये की धनराशि से 'मुख्यमन्त्री सुखाश्रय सहायता कोष' स्थापित करने का निर्णय लिया। इस कोष के माध्यम से मुख्यमन्त्री की इस सकारात्मक सोच को दिशा प्रदान की गई कि जरूरतमन्द बच्चों एवं निराश्रित महिलाओं की सहायता करुणा नहीं अपितु उनका अधिकार है। 'मुख्यमन्त्री सुखाश्रय सहायता कोष' में मुख्यमन्त्री सहित सत्ता पक्ष के सभी विधायक अपना एक-एक माह का वेतन प्रदान करेंगे। विपक्ष के सभी विधायकों से भी इस कोष में धनराशि प्रदान करने का आग्रह किया गया है। दानी सज्जनों और उद्योग जगत से कॉरपोरेट सोशल रिसपान्सिबिलिटी के अंतर्गत कोष के लिए आर्थिक सहायता लेने के प्रयास किए जाएंगे।

शीत ऋतु के दृष्टिगत निराश्रित व्यक्तियों को आसरा प्रदान कर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

प्रदेश सरकार ने अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को 25 हजार रुपये की सहायता राशि तुरन्त जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। अब प्राकृतिक आपदा से प्रभावित मृतक के निकटस्थ सम्बन्धी को 24 घंटे के भीतर सहायता राशि जारी की जाएगी। प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें से 25 हजार रुपये की सहायता राशि 24 घंटे की अवधि में और शेष राशि चार दिन के भीतर जारी कर दी जाएगी। पूर्व में यह राशि जारी होने में अधिक समय लगता था।

मुख्यमन्त्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल एवं संवेदनशील नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता सम्भालने के महज़ एक माह की अवधि में यह सिद्ध कर दिया है कि यह सरकार न केवल समाज के उपेक्षित एवं कमज़ोर वर्गों के सम्मान के साथ जीवनयापन करने के अधिकार को पूर्ण करने की और अग्रसर है अपितु राज्य को गम्भीर वित्तीय स्थिति से उबारने के साथ-साथ उन वायदों को भी पूरा कर रही है जो सरकार और जन-जन के मध्य विश्वास का आधार हैं। सरकार के यह सामाजिक सरोकार सभी में नव-उत्साह का संचार कर रहे हैं।

# निर्माण कार्यों में गति लाने के लिये अभियंताओं की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई

**शिमला/शैल।** प्रदेश में निर्माण कार्यों के लिए सीमिति समयावधि उपलब्ध होने के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से जहां एक ओर फील्ड स्तर पर तैनात अभियंताओं की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई हैं, वहीं निविदा प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय सीमा घटाई गई है।

अब अधिशाषी अभियंता को 2 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। अधीक्षण अभियंता की शक्तियां बढ़ाकर 6 करोड़ रुपये कर दी गई हैं। 6 करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों के लिए मुख्य अभियंता सक्षम होंगे।

पहले निविदा प्रक्रिया में 60 दिन का समय लग जाता था। अब विभाग ने नई समय सीमा निर्धारित की है, जिसके अनुसार निविदा ऑनलाइन रूप में प्राप्त करने के लिए 10 दिन की अवधि होगी। निविदाएं प्राप्त करने के 10 दिन के भीतर अधिशाषी अभियंता द्वारा स्वीकृति पत्र (अवार्ड लेटर) जारी किया जाएगा। यानि ऑनलाइन प्रकाशन के 20 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा। यदि मामला 2 करोड़ रुपये से ऊपर अधीक्षण अभियंता के स्तर का हो तो 10 दिन निविदा प्राप्त करने के लिए, 7 दिन अधिशाषी अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए और 10 दिन अधीक्षण अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानि ऑनलाइन प्रकाशन के 27 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा।

यदि मामला 6 करोड़ रुपये से ऊपर मुख्य अभियंता के स्तर का है तो 10 दिन निविदा प्राप्त करने के लिए, 7 दिन अधिशाषी अभियंता के स्तर पर, 5 दिन अधीक्षण अभियंता के स्तर पर और 8 दिन मुख्य अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानि ऑनलाइन प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा।

निर्धारित समय सीमा में कार्य का आवंटन किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी स्तर पर निर्धारित समयावधि का पालन नहीं किया गया तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध सख्त कारवाई की जा सकती है। इस विषय में फील्ड अधिकारियों की परफॉरमेंस देखी जाएगी और उसके अनुरूप उनकी एसीआर ग्रेडिंग में भी प्रविष्टि की जाएगी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए इन सुधारों से अनुमान है कि निविदा प्रक्रिया में और पारदर्शिता आएगी तथा कार्य दक्षता भी बढ़ेगी। प्रदेश में विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे निर्माण कार्यों को और गति मिलेगी।

# वर्ष 2024 तक पूरे प्रदेश में उपलब्ध होगी 5जी सुविधा:डॉ. अभिषेक जैन

**शिमला/शैल।** सूचना प्रौद्योगिक विभाग वर्ष 2024 के अंत तक हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 5जी सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि लोगों को और बेहतर और सुसंगत इंटरनेट सुविधा प्रदान की जा सके।

सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी डॉ. अभिषेक जैन ने 2024 तक राज्य में 5जी सेवाओं को कार्यशील बनाने के लिए दूरसंचार संरचना स्थापित करने में सरकारी बुनियादी ढांचे के उपयोग के तौर-तरीकों पर राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में डेटा सभी क्षेत्रों में दक्षता और गति के साथ काम करने के लिए अनिवार्य है। यह दूरसंचार क्षेत्र और 5जी सेवाओं के विकास के बिना संभव नहीं है। प्रदेश सरकार दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। प्रदेश में 5जी सेवा कार्यशील करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि सरकारी अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं को निर्धारित समय अवधि के भीतर यह कार्य करने के लिए समन्वय और परिभाषित दृष्टिकोण के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अनुभव किया गया है कि सभी सेवा प्रदाता फाइबर और खंभे स्थापित करने के लिए जमीन खोदते हैं, जिससे लोगों को असुविधा होती है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इसे ध्यान में रखते हुए, उन्हें 5जी सेवा स्थापित करते समय ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए, जिससे प्रकृति व जीवों को कम से कम नुकसान तथा जनता को भी कम से कम असुविधा हो। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी सेवा प्रदाताओं को एक ही बार में समन्वय कर स्थापना कार्य को अंजाम देना चाहिए ताकि दोबारा जमीन खोदने की जरूरत न पड़े।

उन्होंने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र सशक्त होना चाहिए और इसे अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने न केवल व्यावसायिक पहलू पर विचार करने बल्कि लोगों की जरूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दायित्व के साथ कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सेवा प्रदाताओं को सरकार के साथ-साथ निजी संपत्ति को कम से कम नुकसान व पारदर्शिता तथा प्रत्येक हितधारक के अधिकारों पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं को दूर-दराज और बर्फ से आच्छादित क्षेत्रों में सशक्त नेटवर्क कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्य में 5जी सेवा के लिए नीतियों को परिभाषित करने वाली एक प्रस्तुति भी दी।

बैठक में विशेष सचिव सूचना प्रौद्योगिकी टोरुल एस. रवीश, लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास, राजस्व विभाग, विद्युत बोर्ड के अधिकारी और विभिन्न सेवा प्रदाता उपस्थित थे।

# हमें जल उपयोगकर्ता से जल संरक्षण की ओर अग्रसर होना चाहिएः मुकेश अग्निहोत्री

**शिमला/शैल।** उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता मेंजल शक्ति भवन टूटीकंडी शिमला में जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री

ने कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पारदर्शिता, दक्षता व समयवद्धता से अपने कर्तव्य का निर्वहन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रदेश में आमजन को 24 घंटें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की दिशा में भी कार्य करें।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा की हमें जल उपयोगकर्ता से जल संरक्षण की ओर अग्रसर होना चाहिए ताकि भविष्य में जल की कमी न हो। वर्षा एवं हिम जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण एवं स्रोत स्थिरता पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पानी की गुणवत्ता एवं संरक्षण के लिए विभाग को जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पीने के पानी के साथ-साथ हमें सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि किसानों की आय में भी वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि सिंचाई की दृष्टि से बेहतर कार्य करने के लिए रैपिड री असेसमेंट की जाएगी, ताकि जरूरत के आधार पर कार्य किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को हर विधानसभा क्षेत्र में रोड मैप तैयार करने को कहा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 67 प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है, जिसमें से 58 प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विभाग में नई तकनीक के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि विभाग में टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए बीड कैपेसिटी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अधिशाषी अभियंता स्तर के अधिकारी तीन-तीन योजनाओं तथा अधीक्षण अभियंता से प्रमुख अभियन्ता स्तर तक के अधिकारी एक-एक बड़ी योजना एडॉप्ट करें ताकि इन योजनाओं में बेहतर कार्य हो सके।

उन्होंने पुराने कुंओं एवं तालाबों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि विभाग की पुरानी मशीनरी के संरक्षण के लिए किसी संग्रहालय या उपयुक्त जगह का चयन किया जाना चाहिए ताकि हमारी भविष्य की पीढ़ियों को पुरानी मशीनरी व कार्य पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करें ताकि प्रदेश का संतुलित विकास किया जा सके।

इस अवसर पर सचिव जल शक्ति अमिताभ अवस्थी ने उप-मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा उनके निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने का आश्वासन दिया। बैठक में प्रमुख अभियन्ता संजीव कौल, प्रमुख अभियन्ता परियोजना धर्मेंद्र गिल, प्रदेश से सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

# प्रदेश की प्रगति और आर्थिक विकास में उद्योगपतियों का महत्वपूर्ण योगदान:उप-मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोलन जिले के परवाणू में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) तथा परवाणू उद्योग संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रगति और आर्थिक विकास में उद्योगपतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के सर्वांगीणविकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने सत्ता ग्रहण करने के उपरांत जनहित में अनेक महत्वाकांक्षी निर्णय लिए हैं। निर्धन एवं वंचित वर्गों के कल्याण पर विशेषअधिमान दिया जा रहा है। उन्होंने सीआईआई और उद्योग परिसंघ को आश्वासन दिया कि उद्योगपतियों की सभी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। परवाणू उद्योग संघ के सदस्यों ने इस क्षेत्र से संबंधित समस्याओं से उप-मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष इंटक हरदीप सिंह बाबा, नगर परिषद परवाणू की अध्यक्षा निशा शर्मा, उपाध्यक्षा सोनिया शर्मा, सीआईआई के उपाध्यक्ष गगन कपूर, परवाणू उद्योग संघ के अध्यक्ष सुनील तनेजा, हिमाचल प्रदेश गद्दा उद्योग के अध्यक्ष आदित्य सूद, व्यापार मंडल परवाणू के पदाधिकारी, नगर परिषद परवाणू के वार्ड सदस्य, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सोलन सतीश बेरी, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी सोलन संदीप चौहान और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

# एन.एम.एम.ऐप से मनरेगा कामगारों की हाजिरी लगाने के केन्द्र ने दिये राज्यों को निर्देश

**शिमला/शैल।** पंचायती राज विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार ने राज्यों को मनरेगा के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी योजना व परियोजना को छोड़कर) में कामगारों की हाजिरी एन.एम.एम.एस. (नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग ऐप) के माध्यम से लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह प्रावधान एक जनवरी, 2023 से लागू हो गया है। भारत सरकार ने इस संबंध में 23 दिसंबर, 2022 को निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा-27 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्यों को जरूरी दिशा-निर्देश दे सकती है। इसी के तहत भारत सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य करने में सुगमता के दृष्टिगत मनरेगा के तहत कार्य स्थल में नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग ऐप के तहत हाजिरी लगाने का प्रावधान किया है। इससे कार्यक्रम की निगरानी और बढ़ेगी। इस ऐप के प्रयोग से मनरेगा के तहत रोजगार की मांग पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही कार्य स्थल पर कामगारों के लिए किसी तरह की बाधा उत्पन्न होगी बल्कि इससे उन्हें वास्तविक समय में हाजिरी लगाने की सुविधा सुनिश्चित होगी।

उन्होंने बताया कि ऐप के माध्यम से हाजिरी लगाने के लिए राज्य सरकार ने वॉर्ड पंचों को हाजिरी लगाने के लिए प्राधिकृत किया है। यदि कोई वॉर्ड पंच एन.एम.एम.एस. के माध्यम से हाजिरी नहीं लगा पाता है, उस स्थिति में यह कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए स्वयं समूह को दिया जा सकता है। किन्हीं असाधारण परिस्थितियों में किसी तकनीकी कारण से हाजिरी नहीं लगा पाने की स्थिति में हाथ से भी हाजिरी लगाने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 16 मई, 2022 से उन सभी कार्य स्थलों जहां 20 या अधिक कामगारों के लिए मस्टर-रोल जारी किए गए थे, वहां एन.एम.एम.एस. के माध्यम से हाजिरी लगाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को पंचायत स्तर पर एक व्हाट्स-ऐप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया है। इस ग्रुप में निर्वाचित प्रधान, वॉर्ड सदस्य, क्षेत्र के विधायक, सांसद, जिला परिषद् सदस्य, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, इन जनप्रतिनिधियों के चुनाव में प्रथम उप-विजेता, ग्राम रोजगार सेवक व पंचायत सचिव को ग्रुप का सदस्य बनाया जाएगा।

संबंधित पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक या पंचायत सचिव ग्रुप में सभी कार्य स्थलों में मस्टर-रोल जारी करने के बारे में संदेश प्रेषित करेंगे जिसमें सामुदायिक कार्यों के नई मस्टर-रोल जारी करने, मस्टर-रोल जारी करने की तिथि, कार्य कोड, कार्य का नाम तथा मस्टर-रोल के लाभार्थियों के नाम का विवरण भी होगा।

# युवाओं को कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय से जुड़ने के लिए करेंगे प्रेरित:चंद्र कुमार

**शिमला/शैल।** कृषि तथा पशुपालन मंत्री चौ. चंद्र कुमार ने कहा है कि किसानों को आधुनिक तकनीकें उपलब्ध करवाने के साथ लोगों की कृषि और पशुपालन व्यवसाय में रुचि बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे। ताकि वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन सकें। यह विचार उन्होंने ज्वाली विश्राम गृह में अधिकारियों तथा लोगों को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। इस मौके पर एसडीएम मोहिंद्र प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी मण्डलाध्यक्ष चैन सिंह गुलेरिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी तथा गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कृषि मंत्री ने कहा कि खेती की विभिन्न किस्मों को उगाने के प्रति किसानों को प्रेरित करने हेतु जहां कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेतों में जाकर मिट्टी की जांच सुनिश्चित की जाएगी वहीं पैदावार को बढ़ाने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक से खेतीबाड़ी करने बारे भी लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषकों और पशुपालकों के समग्र विकास के लिये प्रदेश सरकार द्वारा ठोस नीति लायी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों को बेसहारा पशुओं तथा जंगली जानवरों से बचाने के लिए एक निर्णायक नीति बनाना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं लंबे समय तक कृषि से जुड़े रहे हैं इसलिए कृषकों की समस्याओं को भली भान्ति जानते हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों पर घूम रहे पशु जहां लोगों की फसलों को उजाड़ रहे हैं वहीं दुर्घटनाओं का भी कारण बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पशुओं की पहचान के लिए टैगिंग की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा ताकि उसके असली मालिक की पहचान कर उसे जुर्माना लगाया जा सके।

उन्होंने कहा कि कृषि तथा पशुपालन हर प्रकार से लाभ का व्यवसाय है लेकिन आज कि पीढ़ी इसमें रुचि नहीं दिखा रही है। उन्होंने बताया कि युवा पीढ़ी को कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे। ताकि वे अपने अन्य कार्यों के साथ इन व्यवसायों को अपना कर लाभ कमा सकें।

कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विशेषज्ञों से किसानों की खेतीबाड़ी सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए नियमित रूप से खेतों में जाकर निपटारा करने के भी निर्देश दिए।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चुनाव से पहले प्रतिज्ञा पत्र में दी गई सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की ओपीएस बहाल करने की मांग को पूरा कर उनसे किये गए वायदे को पूरा कर सबसे बड़ा तोहफा दिया गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को सड़कों के बेहतर रखरखाव, पानी तथा बिजली की नियमित आपूर्ति के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर बनाये रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों से पूरी लग्न, निष्ठा तथा ईमानदारी से कार्य करने तथा आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के भी निर्देश दिए।

कृषि मंत्री ने इस मौके पर लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया। जबकि शेष समस्याओं के शीघ्र समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए।

# एचआरटीसी द्वारा अधिसूचित ढाबे उपलब्ध करवाएं गुणवत्तापूर्ण भोजन

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि यात्रियों द्वारा एचआरटीसी अधिसूचित ढाबों व रेस्तरां में खराब गुणवत्ता वाला भोजन परोसे जाने के विषय में प्राप्त हो रही प्रतिक्रियाओं पर संज्ञान लेते हुए सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों को समय-समय पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रबन्ध निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि एचआरटीसी बसों में प्रदेश के भीतर और बाहर यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिसूचित ढाबे व रेस्तरां में गुणवत्तापूर्ण व उपयुक्त दरों पर भोजन परोसा जाये।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा अम्बाला के समीप मयूर ढाबे के खिलाफ यात्रियों द्वारा खराब व निर्धारित दरों से अधिक दरों पर भोजन परोसे जाने बारे शिकायत पर कारवाई करते हुए विभाग द्वारा मयूर ढाबे को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ढाबा मालिकों को ढाबों में सफाई व गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा भोजन की निर्धारित दरों की सूची प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

संदीप कुमार ने कहा कि राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को शुद्ध, स्वच्छ और निर्धारित दरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करवाना विभाग की प्राथमिकता है और इस दिशा में विभाग हर संभव प्रयास करेगा।

# अवैध खनन गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए उठाए जा रहे कड़े कदम:मुकेश अग्निहोत्री

**शिमला/शैल।** उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने घालूवाल में लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा भी की।

इस दौरान उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में खनन माफिया काफी सक्रिय रहा है और इन गतिविधियों पर पूर्ण रूप से नकेल कसना सरकार की प्राथमिकता है। अवैध खनन पर रोक लगाने और नशीले पदार्थों के खिलाफ शीघ्र ही एक निर्णायक अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को खनन माफिया पर भी कड़ी नज़र रखने तथा नशे की रोकथाम के प्रति जागरूकता अभियान चलाने और इस तरह के मामलों को पड़ोसी राज्यों से भी उठाने के निर्देश दिए।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि स्वां नदी के तटीयकरण पर 1500 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं और इसे नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी पेयजल स्त्रोतों से संबंधित किसी भी सरकारी सम्पति को हानि पहुंचाने संबंधी मामलों की भी तुरंत सूचना दें और आवश्यक कारवाई भी अमल में लाएं।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि बीत क्षेत्र में लगभग 80 करोड़ रूपये की सिचाई योजना निर्मित की जाएगी, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए तथा पेयजल स्त्रोतों की वस्तुत: स्थिति से अवगत करवाने को कहा।

मुकेश अग्निहोत्री ने लोक निर्माण विभाग को प्रदेश के सबसे लंबे हरोली-रामपुर पुल पर तय समय अवधि के भीतर सोलर लाईट लगाने का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पंडोगा-त्यूड़ी प्रस्तावित पुल की भी डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही हरोली में आधुनिक कॉलेज बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि हरोली स्वास्थ्य संस्थान में चिकित्सीय सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। इस अवसर पर उपायुक्त राघव शर्मा, एसपी अर्जित सेन, प्रदेश कांग्रेस सचिव सतीश बिट्टू, अशोक ठाकुर, जिला प्रधान रणजीत राणा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनोद बिट्टू, युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत राय, प्रदेश महिला मोर्चा सचिव सुभद्रा देवी के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

# मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भू-धंसाव संभावित स्थानों की पहचान करने के दिए निर्देश

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भू-धंसाव तथा हिमाचल प्रदेश में ऐसे संभावित स्थानों की पहचान करने पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को आपदा के दृष्टिगत आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने तथा पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने किन्नौर, कुल्लू, चम्बा तथा कांगड़ा जिला के उपायुक्तों को भू-धंसाव के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने तथा रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को भू-स्खलन तथा भू-धंसाव व सड़क हादसों के ब्लैक स्पॉट्स की अलग-अलग रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने प्रदेश में विभिन्न आपदाओं से होने वाले नुकसान की विस्तृत जानकारी भी ली। उन्होंने आपदाओं से निपटने के लिए संस्थागत स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक तैयारियों को मजबूत करने व शमन और निवारक उपायों पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश में भूस्खलन प्रभावित स्थलों तथा सिंकिंग जोन का पूर्ण विवरण लिया। उन्होंने इन क्षेत्रों में जोखिम

न्यूनीकरण तथा आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत समय-समय पर किए गए विभिन्न उपायों का ब्यौरा भी लिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ग्लेशियर मैपिंग के लिए भी आधुनिक उपकरणों के माध्यम से उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में भूकंप अधिक आते हैं उनका अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिन क्षेत्रों में सर्प दंश की घटनाएं अधिक होती हैं वहां इसके उपचार के लिए प्राथमिक स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ऐसे सभी संभावित क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थानों में विषरोधक इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा राज्य आपदा मोचन बल की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई भूमि की वन स्वीकृतियां प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि केन्द्र सरकार से सभी विकास परियोजनाओं की वन स्वीकृतियों के संबंध में मामला उठाया जा सके। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर ऐसे मामलों को निपटाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा मोचन निधि से हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को दी जाने वाली राशि में वृद्धि के भी निर्देश दिए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली में संशोधन के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए।

प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने प्रदेश में भूस्खलन प्रभावित स्थानों तथा आपदा प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने राज्य आपदा मोचन निधि व राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के बारे तथा इससे जिलों को जारी की गई राशि के बारे में भी अवगत करवाया।

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल, विधायक सुरेश कुमार, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, विशेष सचिव आपदा प्रबंधन सुदेश कुमार मोख्टा तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सोलन, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर तथा चंबा जिला के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

# सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कारवाई के निर्देश

**शिमला/शैल।** मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश में चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उन्मूलन से संबंधित कार्ययोजना की समीक्षा की गई।

प्रबोध सक्सेना ने कहा कि राज्य में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। उन्होंने सभी विभागों से आग्रह किया कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में विशेष अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करें ताकि इसके उपयोग को पूरी तरह से बन्द किया जा सके। उन्होंने शहरी विकास और अन्य संबंधित विभागों को फिल्ड निरीक्षण बढ़ाने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग करने वालों के विरूद्ध कड़ी कारवाई के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष तौर पर निगरानी बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि उपायुक्त अपने संबंधित जिले में इस कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि डाटा संकलन और निगरानी के साथ ही जागरूकता पैदा करने और क्षमता निर्माण पर भी बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी एवं अर्ध-सरकारी तथा अन्य विभिन्न संगठनों के कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों के उपयोग को कम कर इसके उन्मूलन के लिए कदम उठाना सुनिश्चित करें।

प्रबोध सक्सेना ने कहा कि जिला, शहरी निकाय तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सभी चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर रोक संबंधी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए नवोन्मेष को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

निदेशक पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ललित जैन ने राज्य में विस्तृत कार्ययोजना के क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के उपयोग पर संबंधित प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों के खिलाफ कारवाई करते हुए चालान के माध्यम से लगभग 13.50 लाख रुपये वसूल किए गए।

बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

**ROPEWAYS & RAPID TRANSPORT SYSTEM DEVELOPMENT CORPORATION H.P.LTD. (RTDC)**

RTDC (A Government of Himachal Pradesh Undertaking)
Ropeways and Rapid Transport System Development Corporation HP Ltd.
प्रदूषण मुक्त यातायात के लिए हिमाचल की पहल

**RTDC MISSION**

**RTDC is the nodal agency of Himachal Pradesh Govt. for the development of ropeways and other innovative transportation system on PPP/Turn key funding mode and to the decongest major urban hubs in the state by the devising innovative transport solutions, to provide connectivity to unexplored new places of tourist interest, all weather connectivity to tough areas.**

RTDC is working to provide connectivity through ropeways, decongest urbans hubs through transport solutions and constructing Pre-Engineered structures which are light weight thermally & accoustically insulated and are quickly constructed. The expected life span of these energy efficient earthquake resistant building is 100 years. Some of these Projects are:

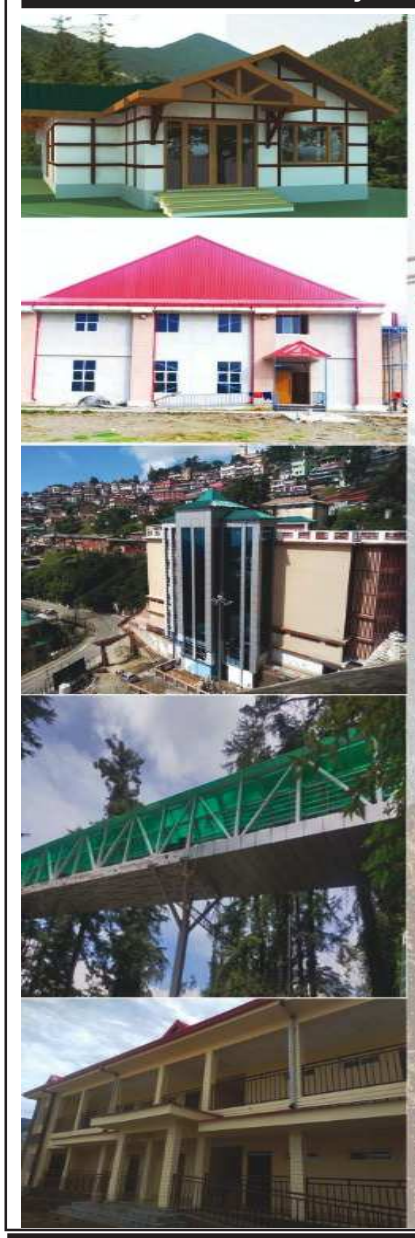

- INNOVATIVE URBAN TRANSPORT SOLUTION BY ROPEWAYS IN SHIMLA
  COST : 1546 CR.
- DEVELOPMENT OF PASSENGER ROPEWAY FROM JABLI VILLAGE TO KASAULI DISTT. SOLAN (H.P.)
  COST : 206 CR.
- DEVELOPMENT OF PASSENGER ROPEWAY FROM NARKANDA TO HATU PEAK IN DISTT. SHIMLA (H.P.)
  COST : 173 CR.
- DEVELOPMENT OF PASSENGER ROPEWAY PROJECT AT BIR BILLING
  COST : 130 CR.
- DEVELOPMENT OF PASSENGER ROPEWAY FROM PALAMPUR. THATRI-CHAUGAN GLACIER DISTT. KANGRA
  COST : 605 CR.
- DEVELOPMENT OF PASSENGER ROPEWAY FROM BIJLI MAHADEV IN DISTT.TO KULLU
  COST : 200 CR.
- DEVELOPMENT OF PASSENGER ROPEWAY FROM BHARMOUR TO BHARMMANI MATA CHAMBA DISTT. MANDI (H.P.)
  COST : 112 CR.
- DEVELOPMENT OF PASSENGER ROPEWAY FROM BAIRAGARH CHAMBA SIDE TO KILLAR OVER SAACH PASSES IN DISTT. CHAMBA (H.P.)
  COST : 1618 CR.
- DEVELOPMENT OF PASSENGER ROPEWAY FROM NATIONAL HIGHWAY (NEAR PANDOH DAM) TO BAGLAMUKHI MATA TEMPLE (BHAKLI) DISTT. MANDI H.P.
  COST : 48.65 CR.
- CONSTRUCTION OF PRE -ENGINEERED MULTIPURPOSE INDOOR SPORTS STADIUM AT NURPUR
  COST : 12.99 CR.
- CONSTRUCTION OF PRE -ENGINEERED ITI COLLEGE AT SAIRI
  COST : 7.8 CR.
- CONSTRUCTION OF PRE -ENGINEERED ENGINEERING COLLEGE AT JEORI
  COST : 22 CR.
- CONSTRUCTION OF FOOT OVER BRIDGE AND LIFT AT VIKASNAGAR .
  COST PHASE I, II & III : 12 CR.

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

# क्या भाजपा की हार के लिए नड्डा और अनुराग ज्यादा जिम्मेदार है जयराम के नेता प्रतिपक्ष बनने से उभरी चर्चा

- ✔ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रदेश भाजपा में बड़े बदलाव के संकेत
- ✔ नड्डा और अनुराग दोनों के प्रभावित होने की संभावना
- ✔ पार्टी की हार से जयराम के सारे प्रतिद्वन्दी हुए प्रभावहीन

**शिमला/शैल।** हिमाचल में भाजपा और जयराम सरकार के हार के कारणों पर अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक विश्लेषण सामने नही आया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री शान्ता कुमार जो अब मार्गदर्शक मण्डल के सदस्य हैं उन्होंने एक ब्यान में अवश्य कहा है कि भाजपा को भाजपा ने ही हराया है। पूर्व मुख्यमन्त्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी भीतरघात

की बात कर चुके हैं। पूर्व मन्त्री और पूर्व अध्यक्ष रहे चुके सुरेश भारद्वाज भी पार्टी के चुनाव प्रबन्धन तथा अन्तिम क्षणों में चुनाव क्षेत्रों को बदलने जैसे फैसलों पर सवाल उठा चुके हैं। पार्टी की परिवारवाद की अवधारणा पर भी सवाल उठाते हुये हार के कारणों के विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर दे चुके हैं। लेकिन इस सबके बावजूद अभी तक औपचारिक रूप से कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। इस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के बिलासपुर से ताल्लुक रखते हैं। इसी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ताल्लुक रखते हैं। इस संसदीय क्षेत्र में ही सत्रह में से केवल पांच पर भाजपा को जीत हासिल हुयी है। मण्डी संसदीय क्षेत्र को छोड़कर शेष पूरे प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन शर्मनाक रहा है। अब नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद प्रदेश संगठन में भारी बदलाव देखने को मिलेगा बल्कि नड्डा और अनुराग ठाकुर पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है। हिमाचल की हार के कारण नड्डा को अभी दूसरा कार्यकाल मिलना कठिन माना जा रहा है।

लेकिन दूसरी ओर प्रदेश में हार के बाद नेता प्रतिपक्ष के लिये जयराम ठाकुर की जगह सतपाल सत्ती और विपिन परमार के नाम चर्चा में आ गये थे। परन्तु जयराम ठाकुर ने विधायकों की शपथ से पहले ही अपने को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की सफल व्यूह रचना कर डाली। बल्कि नेता प्रतिपक्ष की मान्यता तक हासिल कर ली। यही नहीं अपने विश्वस्त रहे अधिकारियों की ताजपोशी भी कांग्रेस सरकार में करवा ली। मन्त्रीमण्डल बनने से पहले ही सरकार के फैसलों पर प्रदेश भर में धरने प्रदर्शनों का विषय बना दिया। मामले को उच्च न्यायालय तक पहुंचा दिया। इस समय विपक्ष सरकार पर लगातार प्रभावी भूमिका में चल रहा है। मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को भी उच्च न्यायालय में ले जाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस को बतौर विपक्ष जयराम की सरकार पर प्रभावी होने के लिए लम्बा समय लगा था। लेकिन जयराम को पहले ही दिन मुद्दे मिल गये हैं। अब इन मुद्दों को लगातार जिन्दा रखना कठिन नहीं होगा।

दूसरी और पार्टी की हार के लिये जयराम से ज्यादा जगत प्रकाश नड्डा और अनुराग पर आरोप लगने लग गये हैं। क्योंकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा हार मिली है। नादौन में अमित शाह की चुनावी जनसभा के बावजूद हार के लिये मण्डल इकाई ने एक पत्र लिखकर सारी जिम्मेदारी यहां से ताल्लुक रखने वाले राज्यसभा सांसद हमीरपुर के नाम लगा दी है और सिकन्दर को अनुराग का करीबी करार दे दिया है।

सुरेश भारद्वाज जैसे नेताओं को के अन्तिम क्षणों में चुनाव क्षेत्र बदलने के फैसले राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के नाम लगा दिये गये हैं। जब सरकार में नेतृत्व परिवर्तन या मन्त्रीयों की छन्टनी करने और उनके विभाग बदलने की चर्चाएं उठती थी तो उन्हें नड्डा के नाम पर शान्त करवा दिया जाता था। अन्त में चुनाव क्षेत्र बदलने के शिकार हुये नड्डा के करीबी राकेश पठानिया। स्वयं को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार मानने वाले सुरेश भारद्वाज। पूरे कार्यकाल में हर मुद्दे पर जयराम को गुमराह करने का आरोप झेलते रहे सबसे ताकतवर नेता महेन्द्र सिंह का टिकट काटकर उन्ही के बेटे को टिकट देकर वहां का राजनीतिक गणित बदल गया। क्योंकि शुरू में ही भाई-बहन का राजनीतिक टकराव शान्त करने में ही महेन्द्र सिंह की सारी ताकत लग गयी। इस तरह अनायास ही पार्टी के भीतर बैठे जयराम के सारे प्रतिद्वन्दी अपने-अपने चक्रव्यूह में ही उलझ कर रह गये। जयराम इस शतरंज में कैसे नेता प्रतिपक्ष का पद झटक गये इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया और बतौर नेता प्रतिपक्ष वह सरकार को कैसे घेरते

हैं और लोकसभा चुनाव में उसका

प्रदर्शन कैसा रहता है यह देखना दिलचस्प होगा।

# भाजपा मुख्यालय से सात सौ मीटर दूर हो रहा निर्माण सवालों में

**शिमला/शैल।** एन.जी.टी. के आदेश के बाद शिमला में नये निर्माणों पर रोक है। कोर ग्रीन और फॉरेस्ट एरिया में तो नये निर्माण किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। इन क्षेत्रों में केवल पुराने निर्माणों की मुरम्मत या गिरने की सूरत में पुराने नक्शे के मुताबिक ही निर्माण की अनुमति मिल सकती है। अन्य क्षेत्रों में केवल अढ़ाई मंजिल के निर्माण की ही अनुमति मिल सकती है। इसके लिये भी दो कमेटियां गठित हैं। उनकी अनुमति के बाद ही निर्माण का नक्शा नगर निगम से पास होगा। एन.जी.टी. के इस आदेश पर जोशीमठ त्रासदी के बाद अमल कड़ाई से होने की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं।

लेकिन इसी दौरान शिमला में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय दीप कमल से महज सात सौ मीटर दूर जंगल में हो रहा निर्माण चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में निर्माण पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। चर्चा है कि इस निर्माण के लिये राजस्व विभाग के साथ मिलकर इस जगह की राजस्व रिकॉर्ड में किस्म बदली गयी है। यह भी चर्चा है कि निर्माण के लिये कई छोटे पेड़ों की बलि दी गयी है। रोचक यह है की निर्माण स्थल पर न तो किसी भाजपा नेता की नजर पड़ी और न ही पुलिस या अन्य किसी प्रशासन की। नगर निगम शिमला के चौकस प्रशासन की भी नजर से यह निर्माण अब तक ओझल चल रहा है। या अपरोक्ष में उसके आशीर्वाद से चल रहा है यह तो किसी जांच से ही सामने आयेगा।